893/883

जनसत्ता/ पृष्ठ10
01-07-2014

फसलों का नुकसान रोकने पर हो बजट में जोर: कृषि विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 30 जून (भाषा)। खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ते दबाव के बीच कई प्रमुख कृषि विशेषज्ञों ने आगामी बजट में खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, जल संरक्षण और फसल कटाई के बाद होने वाले कृषि उपजों के नुकसान को कम करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। इन विशेषज्ञों ने देश भर में मृदा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने व किसानों की आय सुरक्षा के उपाय किए जाने का भी सुझाव दिया है।

सरकार के समक्ष महंगाई, खासतौर से फल-सब्जियों की महंगाई पर काबू रखना बड़ी चुनौती बनी हुई है। मई में खुदरा मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़ कर 8.3 फीसद थी, जबकि उपभोक्ता मूल्य आधारित खाद्य मुद्रास्फीति 9.6 फीसद रही।

मशहूर कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने राजग के पहले बजट से अपेक्षा के बारे में पूछे जाने पर कहा- 'बेहतर फसल के लिए मृदा का स्वास्थ्य होना जरूरी है और खाद्य सुरक्षा के लिए यह अहम है। इसकी अहमियत इस बात से साबित होती है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2015 को 'अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया है। हम देश के हर प्रखंड में मृदा स्वास्थ्य निगरानी एवं सुधार केंद्र स्थापित कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य निगरानी के लिए प्रभावी नई प्रौद्योगिकी अब उपलब्ध है और हर केंद्र की लागत करीब 50 लाख रुपए पड़ेगी।

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने की जरूरत को रेखांकित करते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि फसल कटाई के बाद उसके बेहतर रखरखाव संबंधी ढांचागत सुविधा के अभाव में बड़ी मात्रा में कृषि उपज खराब होती है। उत्पाद और फसल कटाई प्रौद्योगिकी के बीच अंतर है। हम इस अंतर को अति आधुनिक अनाज भंडारण ढांचा तैयार कर दूर कर सकते हैं। स्वामीनाथन ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी ये सुझाव भेजे गए हैं।

बंगलूर स्थित इंस्टीट्यूट फार सोशल एंड इकोनामिक चेंज के एग्रीकल्चर डवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफार्मेशन सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने बजट को लेकर उम्मीद के बारे में कहा कि भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या बुनियादी ढांचे की कमजोरी है। सिंचाई, बाजार और परिवहन संबंधी ढांचागत सुविधाओं की कमी से खेती-बाड़ी की लागत अधिक है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में नुकसान 40 से 50 फीसद है। इसका कारण फसल कटाई के बाद की रखरखाव व्यवस्था, बेहतर परिवहन सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज, गोदामों आदि की कमी है। बजट में इसे दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए।

कुमार ने कहा कि दलहन के मामले में पिछले 30 साल में उत्पादकता में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण प्रौद्योगिकी की कमी है। ऐसे में उत्पादन बढ़ाने के लिए शोध एवं विकास पर ध्यान देने की जरूरत है।

कुमार ने कहा कि फल व सब्जियों के मामले में अगर हम केवल बर्बाद होने वाले फसल का दो तिहाई हिस्सा ही बचा लें तो कीमत काफी हद तक नीचे आ जाएगी और किसानों का मुनाफा भी बढ़ेगा।

प्रख्यात अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईके अलघ ने भी जल संरक्षण के साथ सिंचाई पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने दलहन पैदावार बढ़ाने के साथ साथ कृषि विविधीकरण पर जोर दिया है।

सिंचाई के बारे में कुमार ने कहा कि करीब 60 फीसद कृषि कार्य मानसून पर निर्भर है। वहीं दूसरी तरफ सिंचाई का तरीका पुराना है जिसमें काफी मात्रा में पानी बर्बाद होता है। ऐसे में बजट में टपक सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, संरक्षित खेती जैसी जल बचाने वाली प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे दीर्घकाल में कृषि ज्यादा टिकाऊ होगा। आय सुरक्षा मजबूत करने के बारे में दिए अपने सुझाव में स्वामीनाथन ने कहा कि कृषि उत्पादों पर आधारित ज्यादा से ज्यादा गैर कृषि रोजगार पैदा कर यह किया जा सकता है।

मालूम हो कि नए कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने पदभार संभालने के बाद कहा था कि किसान तभी खेती-बाड़ी में रुचि रखेंगे जब उनके निवेश पर कमाई की गारंटी होगी। उन्होंने कहा था कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी और पिछले 5-7 साल में उनकी औसत आय का निर्धारण करने के बाद बीमा योजना शुरू करेगी।

सुनीता गुप्ता 1/7/14
पत्रिका एवं समाचार पत्र अनुभाग

प्रतिलिपि:-
1. निदेशक कार्यालय
2. संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. अधिष्ठाता/संयुक्त निदेशक (शिक्षा)
4. प्रभारी पी. पी. आई.
5. प्रभारी यू. एस. आई.
6. प्रभारी कैटेट